SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Sir, I do not really see the question in the remarks of the hon. Member.

MR. CHAIRMAN : He says : has this happened any time before? *(Interruptions)*. He says : it is unprecedented in the history of Civil Aviation. *(Interruptions)*.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Sir, there are hundreds of aerobridges all over the world and the essential principle behind the engineering and mechanics is that there is always an outside possibility of an equipment failing. There is always a possibility in any particular type of equipment.

We will certainly try and take great care, Sir. Action against those responsible for this malfunctioning and who were not there to supervise at the time of malfunctioning, is certainly being taken.

SHRI JOHN F. FERNANDES : Sir, whenever there is any accident or tragedy, it is a common fact that the buck is passed on by the Ministry to the DGCA. The DGCA is a department within the Ministry and they cannot be unbiased about it. So, I don't think it is ethical and there is any natural justice. I would like to know from the hon. Minister whether they contemplate to have any other investigative authority with proper powers outside the Ministry. So that there can be a better fair play in the interest of air safety.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Sir, the hon. Member has asked about the question of DGCA operating in an unbiased manner. I can assure him that it is manned by very competent officers and no compromise is done or no other consideration is kept in mind when coming to a final report on any air safety problem. Just for the information of the hon. Member, I know in the Railways, the Commissioner of Railway Safety goes into major railway accidents and that the Commissioner, Railway Safety, comes under the Ministry of Civil Aviation and therefore, it is independent from the Railways. Similarly, in Civil Aviation too, whenever there is a major accident, there is normally a High Court Judge who sits on an enquiry, who is totally independent. So any matters of major safety are always looked after by a more or less independent and autonomous type of agency.

दिल्ली में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों को हुआ घाटा

*102 **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन विभाग के अंतर्गत दिल्ली में जो होटल हैं उन्हें लगातार घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्रमशः 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक होटल को कितना-कितना घाटा हुआ ;

(ग) उसके क्या कारण हैं और क्या उसे दूर करने के लिए सरकार ने कोई उपाय किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI M. O. H. FAROOK) : A statement is laid on the Table of Sabha.

Statement

(a) and (b) The Central Department of Tourism does not operate hotels. However, ITDC is presently operating 8 hotels in Delhi. The information of their profit/loss during last 3 years is as under :—

(Rs. in lakhs).

	Net Profit/loss		
	1989-90	1990-91	1991-92 (Provisional)
1. Ashok Hotel, New Delhi	233.30	(—)40.36	(—)102.00
2. Samrat Hotel, New Delhi	(—)101.95	(—)235.33	(—)247.33
3. Qutab Hotel, New Delhi	30.41	28.30	(—)13.48
4. Hotel Kanishka, New Delhi	135.35	(—)21.97	(—)37.96
5. Lodhi Hotel, New Delhi	34.79	(—)13.26	16.51
6. Janpath Hotel, New Delhi	53.85	10.42	(—)81.31
7. Ranjit Hotel, New Delhi	(—)27.67	(—)52.47	(—)52.70
8. Ashok Yatri Niwas, New Delhi	124.23	90.83	71.49

(c) and (d) The tourism industry including ITDC hotels as a whole has suffered a set back due to Gulf War and its aftermath and internal disturbances in some parts of the country in 1990-91. The steps being taken by ITDC to improve the financial performance of its hotels *inter-alia* include product improvement, control over expenditure, special package tours, incentives through discounts, marketing and reservation tie-ups, etc.

श्री अनन्त राम जायसवाल : सभापति महोदय, क्या यह सही है कि आई० टी०डी० सी० के होटल और दुकानें वगैरह आई० टी०डी०सी० की स्थापना के बाद से 25 वर्ष तक बराबर नफा देते रहे और यदि हां, तो नफा के रूप में, लाभांश के रूप में, टैक्स के रूप में और फोरेन एक्सचेंज के रूप में अलग-अलग उससे क्या नफ़ा मिला, क्या फायदा मिला ? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या यह सही है कि खाड़ी युद्ध और कश्मीर की वैली में अशान्ति के कारण पर्यटन विभाग में जो घाटे आए थे, क्या वह अब पूरे हो रहे हैं, कमी की तरफ हैं, क्या उनको इस साल पूरा हो जाने की आशा है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : सभापति महोदय, वर्ष 1989-90 का मुनाफा लगभग साढ़े छः करोड़ का था।

श्री अनन्त राम जायसवाल : मंत्री जी, मैंने पूछा है कि 25 साल में क्या लगातार बराबर मुनाफा होता रहा ?

श्री माधवराव सिंधिया : सभापति महोदय, 25 साल का रिकार्ड तो मैं माननीय सदस्य को बाद में दे सकता हूं। ज्यादातर मुनाफा ही रहा है। कभी घाटा भी हुआ है। पिछले तीन वर्ष का जो आपने अपने प्रश्न में पूछा है उसके आंकड़े मेरे पास निश्चित रूप से हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि वर्ष 1989-90 में करीब साढ़े छः करोड़ का मुनाफा हुआ है। आई०टी०डी०सी० के होटल डिवीजन का और इसके पश्चात् 1990-91 में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि खाड़ी युद्ध कारण और हमारे देश में भी आम चुनाव होने के कारण कुछ ऐसे विषय उठाये गये जिससे कुछ जगहों पर अशांति फैली। इसकी एडवर्स रिपोर्टस बाहर भी गयी जिसके कारण काफी कुछ हानि हमारे टूरिज्म को पहुंची है। इसीलिए लगभग 3

करोड़ से ऊपर लास हुआ है 1990-91 में। 1991-92 में प्राविजनल लास लगभग 4 करोड़ के आसपास है। पर जो आशाजनक बात इसमें उभरती है वह यह है कि पिछले 6 महीने में होटल डिवीजन ने लगभग $4\frac{1}{2}$ करोड़ का मुनाफा कमाया है, हालांकि ओवर आल लास वर्ष का, प्राविजनल जो हमारा अंदाज है वह लगभग सवा 4 करोड़ रहेगा। यह अंदाज की बात कर रहा हूं, फाइनल फिगर्स आये नहीं हैं। यह लास लगभग $8\frac{1}{2}$ करोड़ होता पर पिछले 6 महीने में टूरिज्म ने जो पिकअप किया है और उससे जो स्थिति में सुधार आया है इसके कारण लगभग साढ़े 4 करोड़ का मुनाफा होने के कारण यह साढ़े 8 करोड़ से घटकर प्राविजनल लगभग सवा 4 करोड़ तक पहुंचा है।

श्री अनन्त राम जायसवाल : क्या यह सही है कि आई०टी०डी०सी० के होटल और उनकी दुकानों आदि के विकास में सरकार की ही दिलचस्पी नहीं है जिसका पहला सबूत यह है कि बोर्ड के पूरे मेम्बर्स नहीं हैं, यहां तक कि चेयरमैन भी नहीं है और दूसरे यह कि प्लान में इसके विकास और माडर्नाइजेशन के लिए बहुत कम पैसा रखा गया है, लगभग आधा पैसा कर दिया गया है।

श्री माधवराव सिंधिया : यह बात सत्य है कि काफी दिनों से सी०एम०डी० की जगह रिक्त है। पर इसमें पी०एस०बी० पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड हमें एक पैनल भेजता है जिसके बाद हम रिकमेंडेशन पी०एस०बी० को भेजते हैं। 19 फरवरी को पैनल आ गया और 25 फरवरी को एप्वाइंटमेंट कमेटी का प्रोसीजर प्रारम्भ किया गया है और अभी तक फाइल हमारे पास नहीं आई है। यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है।

श्री अनन्त राम जायसवाल : अभी हमारा सप्लीमेंट्री बाकी है।

श्री सभापति : दो सवाल हो गये सप्लीमेंट्री के।

श्री अनन्त राम जायसवाल : एक बाकी है।

श्री सभापति : कैसे बाकी है। हो गये हैं। आप अपने लीडर से पूछ लें। तीन सप्लीमेंट्री कैसे होंगे।

श्री अनन्त राम जायसवाल : तीन नहीं हुए हैं। दूसरा हुआ है, तीसरा हम करने जा रहे हैं . . .

(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : पहले का ए० बी० था।

श्री सभापति : अ, ब, स, द।

श्री अनन्त राम जायसवाल : क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि आई० टी० डी० सी० के असेट्स की फारेन बैंक से जांच करवायी गयी है। अगर जांच करवायी गयी है तो उसमें आपके मंत्रालय के फाइनेंस . . (**व्यवधान**)

श्री सभापति : यह तो दूर से भी नहीं उठता है, कहीं से नहीं उठता है। यह तो नया आपने कर लिया।

श्री अनन्त राम जायसवाल : नया नहीं है। इसी का हिस्सा है। आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री का और अरबन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का इसमें कोई आदमी शामिल नही था, क्या यह रिपोर्ट आपको मिली है? अगर मिली है तो क्या इसको पटल पर रखेंगे और इसी से जुड़ा हुआ सवाल यह है . . . (**व्यवधान**)

श्री सभापति : इतना मैं नहीं करुंगा।

श्री अनन्त राम जायसवाल : अच्छा तो इसका जवाब दीजिए।

श्री सभापति : जितना उससे उठता है उतना जवाब दे दें।

श्री माधवराव सिंधिया : मेरा आपसे यह सबमिशन है कि यह पूर्ण तरह से इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, । यह संबंधित है आई० टी०डी०सी० के होटल के बारे में जो कुछ नेगोशिएशंस चल रहे हैं. . . (**व्यवधान**)

श्री सभापति : अब आप विराजिए।

श्री माधवराव सिंधिया : प्रोफेशनल मैनेजमेंट और आई० टी० डी० सी० का एक संयुक्त प्रयास जो कुछ होटल से संबंधित है यह उसके बारे में है। निश्चित रूप से असेट्स का इवैल्युएशन करना आवश्यक होता है इक्विटी दूसरे को देने से पूर्व, तो वह उस क्वेश्चन से संबंधित है।

श्री दयानन्द सहाय : सभापति जी, यह सबको विदित है कि 5 सितारा होटल हो या 3 सितारा इसमें कौन लोग रहते हैं। इनमें इस देश के बहुत धनी वर्ग के लोग जिनकी संख्या शायद 1 या 2 परसेंट है . . . (**व्यवधान**) मैं तो 1 परसेंट में मानता हूं, वे लोग रहते हैं, उनकी सुख सुविधा के लिए लए. . . (**व्यवधान**) अगर इस होटल के रहने पर जो घाटा होता है सरकारी उत्थान में, यह पब्लिक अंडरटेकिंग्ज में है और फिर उसको हम जनरल बजट से जो पूरा करते हैं, तो देश की पूरी गरीब जनता उसको मदद करे, पूरी गरीब जनता मदद करे और 1 परसेंट से कम लोग उसका फायदा उठायें । . . . (**व्यवधान**)

श्री सभापति : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री दयानन्द सहाय : मेरा प्रश्न यह है कि मंत्री जी इसको माने कि जनरल बजटसे कोई मदद करना अनैतिक है और अगर हम होटल नहीं चला पा रहे हैं, तो क्या मंत्री जी इसको कंट्रैक्ट पर टेंडर निकाल करके इसका मैनेजमेंट प्राइवेट सैक्टर को देंगे ?

यहां पर दिल्ली के होटल 25-25 करोड़ रुपये सालाना प्राफिट करते हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इनसे यही जानना चाहता हूं कि जो दिल्ली में पांच-सितारा या तीन-सितारा होटल हैं, उनका मैनेजमेंट क्या यह प्राइवेट सैक्टर को कंट्रैक्ट पर, लीज पर दे सकते हैं ?

SHRI M. O. H. FAROOK : Sir, I would like to say one thing that there is no budgetary support at all for these hotels from any section. Secondly, I fully agree that we are thinking of going for equity participation and that we are negotiating at that level and when it comes over there we can think of giving management and other levels.

SHRI RAJ MOHAN GANDHI : I would like to know whether the Minister has received any complaints about the Centaur Hotel in Srinagar . . . .

MR. CHAIRMAN : I think the question is about Delhi. प्रश्न दिल्ली के होटल के बारे में है। अगर आप पूरा हिंदुस्तान ले लेंगे. . . (**व्यवधान**) You are a reasonable person.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Can I make a submission ?

श्री सभापति : सवाल दिल्ली के बारे में है, राजधानी के बारे में है।

SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Sir, I make a submission ?

MR. CHAIRMAN : If you both are ready, I have no objection.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA : No, I am not ready. But I want to say that the Centaur Hotel comes under the Hotel Corporation of India which is a subsidiary of Air India, not ITDC. I am happy to discuss it with the hon. Member.

MR. CHAIRMAN : You talk to him. Mr. Ahluwalia.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: सभापति जी मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा—मंत्री महोदय ने

जो लाभ और नुकसान का ब्यौरा दिया है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि दिल्ली शहर में आई०टी०डी०सी० के होटल जो हैं, कभी मंत्री महोदय ने इस पर विचार करने की कोशिश की है क्या पांच-सितारा दिल्ली के आई० टी० डी० सी० के होटल और पांच सितारा दूसरे प्राइवेट कंपनियों के जो होटल हैं, उनमें एफिशेंसी का कितना फर्क है ? उन्होंने तो कह दिया है कि गल्फ वार के कारण और बहुत सारे हालात हमारे मुल्क में पैदा हुए थे, इसलिए टूरिस्ट या विजिटर दिल्ली में नहीं आए और इसलिए होटलों में नहीं ठहरे, इसलिए घाटा हुआ।

पर मैं जहां तक जानता हूं कि आई० टी० डी० सी० के होटलों की एफिशेंसी इतनी खराब है, वहां की सर्विस इतनी खराब है कि कोई भी आदमी, चाहे वह सरकारी हो या गैर-सरकारी, कोई भी हो, आई० टी० डी० सी० के होटल में नहीं जाना चाहता है।

दूसरा, आपने बहुत सारे होटल के एक्सपेंडिचर पर कर लगाये हैं। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, इन्होंने कर लगाये कि यह जो बड़े लोग आकर होटलों में ठहरते हैं, इन पर एक्सपेंडिचर टैक्स लगाना चाहिए और इन पर 15 प्रतिशत का टैक्स भी लगाया, पर इन प्राइवेट होटलों में उन्होंने 20 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक रिबेट भी अपने कस्टोमर्ज को देते हैं।

आज के कंपीटीटिव मार्केट में आई० टी० डी० सी० क्यों नहीं अपने एफिशेंसी में, अपने फर्निचर में और फर्निशिंग में सुधार लाये, वहां की दिखावट और सजावट में भी सुधार लाये और इनके साथ कम्पीट करके मार्केट में मुनाफा कैसे कर सकता है, इसके ऊपर विचार किया है या सर्वे किया है, तो यह बताने की कृपा करें।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, निश्चित रूप से इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है और मैं सोचता हूं कि प्रोफैश्नल मैनेजमेंट भी इसमें सम्मिलित करने का प्रयास जारी है और इसी कारण नैगोसिएशंस एक इंटरनेश्नल होटल चेन के साथ, ताकि एक मार्केटिंग नेटवर्क भी हमें उपलब्ध हो और वर्किंग में भी सुधार आये।

तो यह बात जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से दिल्ली होटल्स में लास हुआ है, पर लास का आधा हिस्सा सम्राट होटल के कारण और सेक्यूरिटी कारणों से 30 प्रतिशत होटल हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। We are not able to use 30 per cent of hotels. That is why there is a loss of about Rs. 2.47 crores out of the total loss of Rs. 450 crore. Because of that also पर सुधार की बहुत ज्याद गुंजाइश है। जहां तक आपने री-इन्वेस्टमेंट की बात की है आर्थिक संसाधनों की काफी कुछ कमी हम महसूस कर रहे हैं। इसलिए यह active participation of professional management का जो एग्रीमेंट होगा उसमें भी हम यही आशा करते हैं कि हमको आर्थिक संसाधन भी मिलेंगे, हमारे जो मैनेजिंग पार्टनर्ज होंगे और उनके द्वारा इनको फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा।

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय मैं मंत्री महोदय से दो बिंदुओं पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। पहला इन्होंने कहा कि यह सच है कि सी०एम०डी० का बहुत दिनों से वहां पर एप्वायंटमेंट नहीं हो सका। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट कोई ऐसा इन-बिल्ट सिस्टम बनायेंगे क्या ऐसा कभी नहीं हो हैड आफ् द डिपार्टमेंट जो रहे वह रिक्त स्थान नहीं रहे ? तो वह जब स्थान रिक्त हो जाता है तो "विनायका ही हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं पहले कि कोई इन बिल्ट सिस्टम ऐसा आप करें। दूसरा, मैं यह चाहता हूं कि क्या कारण है कि वहां के जो मजदूर लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं उनकी यूनियन के साथ जो आपने ये मेजर्ज़ बताए हैं हम अच्छा

करें, क्या कभी आपने उनके साथ डिसकस किया ? यह घाटा लगता है, आखिर कब तक हम लोग नासिक प्रैस से इनको देते रहेंगे ? इसलिए क्या कोई मेमोरेंडम आफ् अंडरस्टैंडिग वहां की ट्रेड यूनियन के साथ करेंगे ताकि यह फिर रेपीटीशन नहीं हो घाटे का ?

श्री माधवराव सिंधिया : यूनियन के साथ चर्चा निरन्तर होती रहती है और डायलाग निरन्तर होता रहता है। हमारा यही प्रयास है कि होटल के हित को ध्यान में रखते हुए हम साथ ही साथ अपने स्टाफ और अपने जो मैनेजमेंट में जो स्टाफ है उसके भी हित को हम देखते रहे। वैसे तो रेश्यो है स्टाफ टू एक्सपेंडीचर . . .

श्री चतुरानन मिश्र : यह मैंने नहीं पूछा। मैंने पूछा कि उन ट्रेड यूनियनों के साथ कोई घाटे के विषय पर मेमोरेंडम आफ् अंडरस्टैंडिंग आप कर रहे हैं ?

श्री माधवराव सिंधिया : मेमोरेंडम आफ् अंडरस्टैंडिंग होने से चर्चा होती रहती है. . . **(व्यवधान)** मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग कोई बात नहीं है।

श्री चतुरानन मिश्र : तो उनके साथ. . . **(व्यवधान)** कब तक हम लोग इस तरह का घाटा, आप ही बताइये हम नासिक प्रैस से कब तक देते रहेंगे ? वर्कर्ज़ पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होने से वह भी उसके लिए साझीदार हो जाएगा।

श्री माधवराव सिंधिया : जो वर्तालाप करेंगे . .

श्री सभापति : इनका प्रश्न जो है वह वर्कर्ज़ पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के बारे में क्या आप सोच रहे हैं ?

श्री माधवराव सिंधिया : जो चर्चा और वार्तालाप जो चलता है वर्कर्ज़ और स्टाफ के साथ उसमें एक प्रमुख बिंदु यह भी है कि घाटा कैसे पार करना और उसके ऊपर सैपेरेट मेमोरेंडम आफ् अंडरस्टैंडिग घाटे के ऊपर कुछ बनाना पड़ेगा . ।. . . (व्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्र : कोई इन-बिल्ट सिस्टम होगा कि सी० एम० डी० का स्थान रिक्त नहीं रहेगा, यह मैंने पूछा ?

श्री माधवराव सिंधिया : यह मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं यह प्रोपर प्लानिंग होनी चाहिए कि किसी का अगर रिटायरमेंट हो रहा हो तो 2-3 महीने पूर्व से ही प्रक्रिया प्रारंभ हो जानी चाहिए और यह जो स्थान है ज्यादा लंबे समय तक रिक्त नहीं होने चाहिए।

It is a question of proper planning. I fully agree that . . .

श्री चतुरानन मिश्र : सहमत तो हैं, लेकिन हम तो एप्वायंटमेंट नहीं करेंगे, यह आप ही को करना है।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं कह रहा हूं हमारी. . .

श्री चतुरानन मिश्र : हमने पूछा कि इन-बिल्ट सिस्टम कुछ होगा ?

श्री माधवराव सिंधिया : होना चाहिए।

श्री चतुरानन मिश्र : होना चाहिए, लेकिन होगा या नहीं होगा ?

श्री माधवराव सिंधिया : सर, मैं इस बात को मान रहा हूं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा।

Favouritism shown by DESU to temporary consumers

*103. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the report appearing in the Hindustan Times of the 14th April, 1992 regarding favouritism shown by DESU to temporary consumers by giving permanent connections without realising the heavy outstanding dues causing financial and legal problems ;